पैराग्वे के एक कानून में दो संशोधनों के बाद वहां के संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा, मैंडानोस डैल चाको नैशनल पार्क ''सार्वजनिक स्थान'' के रुप में नामजद हो जाएगा, जिसके बाद सरकार को उस हाइड्रोकार्बन इण्डस्ट्री में निवेश की छूट मिल जाएगी, जिसे कई वर्ष पहले इस क्षेत्र से निकाला गया था। इसके साथ ही क्षेत्र में खनन व नैचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, जबकि, व्यापक रूप से इस कदम का विरोध किया जा रहा है, यह तर्क देकर कि, इस तरह के विकास से यहाँ का नाज़ुक सवाना इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। ईको डवलपैंट नॉन प्रॉफिट संस्था, ऑल्टा वीडा की प्रोजैक्ट को ऑर्डिनेटर मॉनिका सैन्ट्रन ने कहा, ''ड्रिलिंग होगी, भारी शोषण होगा और अन्य कम्पनियों के लिए भी दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा हुआ तो पार्क नष्ट हो जाएगा।'' देश के उत्तर पश्चिम का यह नैशनल पार्क 605,075 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह नैशनल पार्क एक विशाल बायोस्फियर रिज़र्व का हिस्सा है, जिसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र, जैसे डिफैन्सर्स डैल चाको नैशनल पार्क और बोलीविया का का-ईया नैशनल पार्क भी शामिल हैं। यह पार्क अपने अनूठे, शुष्क जंगल व सवाना इकोसिस्टम के कारण युनैस्को वर्ल्ड हैरिटेज स्टेटस के लिए भी विचाराधीन हैं। इस क्षेत्र की जैव विविधता भी बहुत ज्यादा है। यहां जाएंट आर्माडिलो, पैंटनल कैट और गुआनाको (लामा गुआनिकोई) जैसे जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जलीय चट्टान परत येरुडा और मीठे पानी की टाइमनी नदी भी है। इस पार्क में 130 स्थानीय आदिवासी ग्वारानी नैन्दवा परिवार एवं एयोरेयो कबीले रहते हैं। ये सभी लोग यहाँ के फ्रैश वॉटर रिज़र्व्स पर निर्भर हैं, जो कि भविष्य में होने वाली ड्रिलिंग से जोखिम में पड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में खनन के लिए कई नैचुरल गैस कम्पनियों के पास परमिट है पर 2016 में इन कम्पनियों को अपना काम बंद करना पड़ा था क्योंकि पार्क की सीमा का विस्तार हो गया था और उनका खनन क्षेत्र भी संरक्षित दायरे में आ गया था।

भरतपुर में आरक्षण आंदोलन स्थल के करीब एक आंदोलनकारी ने फांसी लगाकर जान दी

आंदोलनकारियों ने सरकार से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी देने की मांग की

भरतपुर, 25 अप्रेल (निस)। जयपुर-आगरा नैशनल हाइवे पर चल रहे आरक्षण आंदोलन में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब आंदोलन स्थल से कुछ दूरी पर ही एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली।

पुलिस ने मृतक के शव को जिला आर.बी.एम. अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाप्ता भी मोर्चरी में तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि, वैर तहसील के गंधार गांव निवासी मोहन सिंह पुत्र परवाती ने आंदोलन स्थल से कुछ दूरी पर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि, ज्योतिराव फुले अमर रहे । 12 प्रतिशत आरक्षण लेकर रहेंगे। शव की सूचना मिलते ही मौके पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को जिला आर.बी.एम. अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

■ ज्ञातव्य है कि, माली, सैनी, कुशवाह समाज के लोग 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

माली, सैनी, कुशवाह, शाक्य, मौर्य के समाज के लोग 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर 21 अप्रेल से धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों ने पिछले 5 दिनों से नैशनल हाइवे जाम कर रखा। हालांकि माली, सैनी, कुशवाह, शाक्य, मौर्य का प्रतिनिधिमंडल जयपुर गया है। जहां सरकार के साथ उनकी वार्ता अंतिम चरण में बताई जा रही है। माली, सैनी, कुशवाह, शाक्य, मौर्य के प्रतिनिधिमंडल ने लोगों से जाम खोलने एवं आंदोलन स्थल हाइवे से कुछ दूरी पर बनाने की अपील भी की थी।

लेकिन आंदोलनकारियों ने नेताओं की बात अभी तक नहीं मानी है। फिलहाल मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी है। आंदोलनकारियों ने बताया कि, प्रशासन के रवैये से समाज में नाराजगी है। आरक्षण के लिए उसने आत्महत्या कर ली। समाज को 12 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही मोहन के परिजनों को मुआवजा, बेटे को सरकारी नौकरी और मोहन को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि, मोहन सिंह 21 अप्रेल से ही धरना स्थल अरोदा में थे। सोमवार रात खाना खाने के लिए वे अपने घर गंधार गांव चले गए थे। मंगलवार सुबह 4 बजे वे घर से निकल आए और धरना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर पेड़ से रस्सी का फंदा लगाकार जान दे दी। घर में मोहन अकेले कमाने वाले थे। उनके पिता परवाती सिंह का निधन हो चुका है। मंगलवार दोपहर 12 बजे फुले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी की अगुवाई में सैनी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। समाज ने 12 परसेंट आरक्षण की मांग दोहराई। यहां दोपहर 3 बजे तक दो दौर की वार्ता हुई। सैनी ने बताया कि, सरकार ने संघर्ष समिति को लिखित मसौदा दिया है। सरकार ओ.बी.सी. आयोग को पत्र लिखकर समाज की जनसंख्या की गणना कर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति से अवगत कराएगी। 1 मई को प्रशासन के अधिकारियों से बात होगी। आंदोलन खत्म करने और हाईवे खोलने के सवाल पर सैनी ने कहा कि, सरकार की ओर से लिखित मसौदा भरतपुर स्थित धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे साथियों को पढ़ कर सुनाएंगे। वे जो फैसला करेंगे, कमेटी वही मानेगी।

मानहानि मामले में सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दायर की

अहमदाबाद, 25 अप्रेल। 2019 में लोकसभा सभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिया गया एक बयान उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है। इस बयान की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई।

साल 2005 से जिस सरकारी आवास में रह रहे थे, वह खाली करना पड़ा। गुजरात की एक निचली अदालत उन्हें इस मामले में दो साल की सजा सुनाई, जिसे सूरत सेशन कोर्ट ने भी कायम रखा। अब इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है।

जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है।

मंगलवार को उन्होंने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। वहीं इससे पहले 20 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर अपने भाषण में टिप्पणी की थी जिसे लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

■ इस केस के कारण ही राहुल गांधी को संसद की सदस्यता तथा 2005 से प्राप्त सरकारी आवास दोनों खोने पड़े हैं।

दरअसल, 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था।

रणनीतिज्ञों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस मौके पर, कर्नाटक के ए.आई.सी.सी. प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, विधायक यतीन्द्र सिद्धारमैया आदि उपस्थित थे। प्रियंका मैसूर और चामराजनगर जिलों में भी चुनाव प्रचार करेंगी।

कांग्रेस ने 'पी.एम. केअर्स फंड'' पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (वार्ता)। कांग्रेस ने पी.एम. केयर्स फंड को हर स्तर पर मोदी सरकार की निराधार पहल करार देते हुए कहा है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है इसलिए इस बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस निधि में बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देश में इतने बड़े स्तर पर इस निधि से पैसे का आय-व्यय हो रहा है लेकिन इसका न कोई कानूनी आधार है और न इस बारे में विधायिका की कोई अधिसूचना है।

उन्होंने कहा कि पी.एम. फंड या प्रादेशिक फंड सब सूचना के अधिकार के तहत होते हैं लेकिन इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है। इसमें 5900 करोड़ रुपए की रकम सरकारी कंपनियों तथा मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों से आई है लेकिन सरकार कहती है कि इसके लिए कोई बजटीय व्यवस्था नहीं है। पी.एम. केयर्स में 60 प्रतिशत ओ.एन.जी.सी., एन.टी. पी.सी., आई.ओ.सी. के साथ ही सरकार द्वारा संचालित फर्मों से आता है इसलिए इसको लेकर जवाबदेही तथा पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इस बारे में जवाब देगी और श्वेत पत्र जारी करेगी। पी.एम. केयर्स को ज़बरदस्ती, अराजकता, भ्रम और भ्रष्टाचार करार देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कई सवाल उठाए और कहा कि सरकार हर महीने वेबसाइट पर पी.एम. केयर फंड का पूरा खर्चा, प्राप्त राशि, दानदाता का नाम शेयर क्यों नहीं करती है। कैग को रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती है और पारदर्शिता के लिए आर.टी.आई. में रिपोर्ट क्यों नहीं की जाती है। पार्टी ने यह भी पूछा कि किसी अधिनियम के तहत इस बारे में कोई अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गयी है और सरकार इसे कानून का रूप क्यों नहीं देती है।

■ कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने घोटाले की आशंका जताते हुये कहा, इस निधि में बहुत बड़े स्तर पर पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है, लेकिन इसका कोई हिसाब-किताब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

■ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, पी.एम. फंड या प्रादेशिक फंड सब राइट टू इन्फोर्मेशन (आर.टी.ई.) के तहत होते आते हैं, लेकिन ''पी.एम. केअर्स फंड'' के मामले में ऐसा नहीं है। इसको लेकर इस तरह का कोई कानून नहीं है।

शिरोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एक हफ्ते पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पंजाब की राजनीति के पितामह प्रकाश सिंह बादल पांच बार मुख्यमंत्री रहे। 27 मार्च 1970 को जब वे पहली बार मु.मंत्री बने तब उनकी उम्र 42 साल थी। सबसे ज्यादा पांच बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। उनके निधन पर दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।

क्या आनंद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया था। उस वक्त, नीतीश कुमार की पार्टी जे.डी. (यू), भाजपा की गठबंधन सहयोगी थी और प्रकट रूप से मुख्यमंत्री, राज्य के कुल 4 प्रतिशत राजपूत वोट बैंक के समर्थन को लेकर सुनिश्चित थे। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है, ऊंची जातियों में नीतीश कुमार का सपोर्ट बेस घटता नज़र आ रहा है। असउद्दीन ओवैसी की ए.आई.एम.आई.एम. जैसी पार्टियों के राज्य में प्रवेश करने के साथ ही मुस्लिम, ओ.बी.सी. और महादलित वोटर्स पर नीतीश कुमार की पकड़ भी कमजोर पड़ रही है। कोरी जाति के नेता उपेन्द्र कुशवाहा ने जब हाल ही में जे.डी. (यू) छोड़ने और अपनी स्वयं की पार्टी गठित करने की घोषणा की थी, तब कुमार के कुर्मी-कोरी जातिगत प्रबंधन को भी एक झटका लगा था। कुमार कुर्मी जाति से हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि, कुशवाहा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा से जुड़ जाएंगे।

आनंद मोहन सिंह की रिहाई को, राजपूत व ऊंची जातियों के वोटर्स पर थोड़ी पकड़ बनाए रखने और भाजपा के प्रभाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अपना जनाधार बनाने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आनंद मोहन राजपूत हैं और बिहार में राजनीतिक महत्व रखने वाले मिथिलांचल क्षेत्र में उनका गहरा प्रभाव है।

मुसलमानों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था। सरकार के इस कदम को सर्वोच्च न्याायलय में चुनौती दी गई थी और अदालत ने इस केस का फैसला होने तक, इस आदेश के क्रियान्वयन पर स्टे लगा दिया था।

तथापि, इस आदेश पर मिला स्टे भाजपा को और उसके प्रतिद्वंदियों को इस प्रकरण का उल्लेख करने से तो नहीं रोकता और यह तो तय शुदा बात है ही कि, भाजपा ने इस मुद्दे पर चर्चाओं और बहस को ऐसा रूप दिया है कि यह एक चुनावी मुद्दा बन जाए।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''अगर गलती से कांग्रेस सत्ता में आ गई तो भ्रष्टाचार अब तक के सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच जायेगा तथा ''तुष्टीकरण'' शुरू हो जायेगा।''

मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने सरकार की कार्यवाही का बचाव करते हुए कहा कि, इस कार्यवाही से मुस्लिमों के प्रति अन्याय नहीं हुआ क्योंकि आरक्षण के लिये उन्हें ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में जोड़ा गया है।

कर्नाटक सरकार के निर्णय पर घोर आपत्ति जताते हुये, के.पी.सी.सी. अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने भी वादा कर दिया कि, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों का यह आरक्षण फिर से बहाल कर दिया जायेगा।

शिव कुमार ने कहा, ''वे (सरकार) यह सोचते हैं कि, आरक्षण का बंटवारा सम्पत्ति की तरह किया जा सकता है। यह सम्पत्ति नहीं है। यह (अल्पसंख्यकों) का अधिकार है।''

अन्य कांग्रेस नेताओं, जैसे ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, ने भी मंगलवार को कहा कि, भाजपा ने ''कर्नाटक की जनता को धोखा दिया है।'' उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि ''भाजपा की बोम्मई सरकार के ''आरक्षण के फर्जीवाड़े'' की कलई एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में खुल गई है।'' उन्होंने मांग की कि ''प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री बोम्मई जवाब दें कि, उन्होंने वोकलिग, लिंगायत तथा एस.सी./एस.टी. के लोगों के साथ छल क्यों किया क्योंकि भाजपा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णय का कोई बचाव नहीं किया।''

कुछ हिचकिचाहट के बाद अखिलेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिस्सा मिलना ही चाहिये, लेकिन जहाँ अन्य क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहाँ कांग्रेस को उन्हें रास्ता देना ही चाहिये। यही एकमात्र ऐसा रास्ता है, जिस पर विपक्षी गठबंधन काम कर सकता है तथा अन्ततः प्रभावी रहेगा।''

इस बी.आर.एस. नेता ने आगे कहा कि, पार्टी 2024 के लिये नरेन्द्र मोदी बनाम राहुल गांधी चर्चा को लेकर सहज नहीं है। विपक्ष इस विकल्प पर निश्चित रूप से हारेगा। 2019 में इसका परीक्षण हो चुका है। विपक्ष में और भी लोग हैं, जैसे- (बिहार के मुख्यमंत्री) नीतीश कुमार तथा (बंगाल की मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी, जिन्होंने प्रशासन का ट्रैक-रिकॉर्ड बनाया है। राहुल गांधी की उपलब्धि क्या है? वे तो अपनी पार्टी के अधिकृत नेता भी नहीं हैं। और न उनमें इतना साहस है कि वे स्वयं को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर सकें।''

एक अन्य नेता ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुये समझाया कि, विपक्षी एकता का आकार-प्रकार क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, ''कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) से काफी सीटें झटक लीं और अन्त में ''उसे चोट पहुँचाई, जब वह अपने हिस्से की अधिकतर सीटें जीतने में विफल रही।''

सूत्रों ने कहा कि, बी.आर.एस. ''सार्थक'' गठबंधन पर विशेष जोर देती है तथा विपक्ष को एकजुट करने के लिये काम करेगी। सूत्रों ने कहा कि, अगले कुछ महीनों में विभिन्न दलों के बीच होने वाली चर्चाओं के दौरान बहुत सारी चीजें अंतिम रूप ले लेंगी। हाल ही की दिल्ली यात्रा के बाद, जिसमें नीतीश ने विभिन्न दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल थी, के नेताओं के साथ मीटिंग की थी, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि, वे बी.आर.एस. सहित विपक्षी गठबंधन बनाने के लिये अन्य क्षेत्रीय दलों से बात करेंगे। के.सी.आर. के इस नजदीकी नेता ने जोर देते हुए कहा कि, उनकी पार्टी की प्राथमिकता इस वर्ष के अंत में होने वाले ''विधानसभा चुनाव'' हैं। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस का सितारा चमकेगा कि नहीं, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक के विधानसभा चुनावों पर नजर रखी जायेगी। ''इनके परिणाम बातचीत की पृष्ठभूमि का काम करेंगे।''

आम जनता की नजर में, कांग्रेस और बी.आर.एस. कट्टर दुश्मन बने हुये हैं। गत वर्ष अक्टूबर में, राहुल ने टी.आर.एस. का नाम बदलकर बी.आर.एस. किये जाने की हंसी उड़ाई थी तथा कहा था कि, के.सी.आर. अगर चाहें, तो अपनी पार्टी को ''अन्तर्राष्ट्रीय'' कहने के लिये भी स्वतंत्र हैं। बी.आर.एस. ने भी इस पर पलटवार किया था, जिसके अंतर्गत, के.सी.आर. के पुत्र तथा राज्य के मंत्री के तारक रामाराव या के.टी.आर. ने कहा था कि ''प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले'' पहले अमेठी से तो जीत लें (जो उनकी पारिवारिक सीट है तथा जहां से गत चुनाव में राहुल, स्मृति ईरानी से हार गये थे)।

बी.आर.एस. ने कहा कि, ''हमें भाजपा का झूठ उजागर करना है, हमें जनता को सच बताना है। हमें लोगों को यह बताना है कि भाजपा अपने किए गए सभी वादों पर वास्तव में विफल हुई है। हमें यह उजागर करना है कि, चीन सीमा पर किसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया।''

पार्टी सूत्रों ने बताया कि, पार्टी भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और सोशल मीडिया पर उसके होल्ड को देखते हुए, अपने सामने भाजपा की चुनौती से वाकिफ है और उसे बदलने की कोशिश कर रही है। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित होंगे, उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीट शेयरिंग जैसे एकजुटता के कार्य शुरू किए जाएंगे, विपक्ष की एकता की वार्ताएं तभी गति पकड़ेंगी। इस राह में कई समस्याएं हैं। एक नेता ने कहा कि, ये मतभेद बड़े नहीं हैं और कुशल बातचीत के जरिए इन्हें दूर किया जा सकता है।

मादक पदार्थ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। मादक पदार्थों की आसानी से उपलब्धता के चलते युवा वर्ग में इसके सेवन का प्रचलन बढ़ा है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके चलते युवाओं का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी नशा मुक्ति केन्द्र और एन्टी ड्रग्स चौकियां खोलकर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में ड्रग सप्लाई करने वालों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। इसके अलावा अभियुक्त बजरंग को पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में उसने वापस अपराध को दोहराया है। इसलिए उसे अधिक दंड दिया जा रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि, 18 दिसंबर, 2017 को करधनी थानाधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, दो लड़के प्लास्टिक के कट्टों में अवैध गांजा भरकर बेनाड रोड से सरना रीको एरिया में सप्लाई करने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने सरना चौकी चौराहे पर दोनों अभियुक्तों को रोककर तलाशी ली। इस दौरान बजरंग के कब्जे से 9 किलो सात सौ ग्राम और अहसान खान से 9 किलो पांच सौ ग्राम गांजा मिला।

वहीं अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि, उन्हें मामले में फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से उनके खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित नहीं होता है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों की पालना भी नहीं की है। ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

गलवान की झड़प के बाद पहली बार मिलेंगे चीन और भारत के रक्षा मंत्री

चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू 27 अप्रैल को भारत आयेंगे

नई दिल्ली, 25 अप्रेल। चीन ने मंगलवार को कहा कि, रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू 27 अप्रैल से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एस.सी.ओ.) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ली की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता होने की उम्मीद है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी माने जाने वाले जनरल ली की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के मध्य तनावपूर्ण गतिरोध के बीच हो रही है।

चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आमंत्रण पर चीनी स्टेट काउंसलर और रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू 27-28 अप्रैल से नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की परिषद् की बैठक में भाग लेंगे। बयान में कहा गया, ''बैठक के दौरान, जनरल ली सम्मेलन को संबोधित करेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय हालात के साथ-साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग के मुद्दों पर संवाद करने एवं विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए संबंधित देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से मिलेंगे।''

जनरल ली के रक्षा मंत्री सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करने और गतिरोध को हल करने के लिए सैन्य तथा कूटनीतिक वार्ता की प्रगति पर चर्चा करने की संभावना है। जनरल ली के दौरे से पहले, चीनी रक्षा मंत्रालय ने 23 अप्रैल को चुशूल-मोल्दो सीमा स्थल पर आयोजित चीन-भारत कोर कमांडर स्तरीय बैठक के 18वें दौर के बारे में सकारात्मक बात की। चीन ने कहा है कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति कायम करने के अलावा पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी गतिरोध से संबंधित 'प्रासंगिक मुद्दों' के समाधान को ''तेज'' करने पर सहमत हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रासंगिक मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मैत्रीपूर्ण और स्पष्ट विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

■ ली शांगफू 27 अप्रैल से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एस.सी.ओ.) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान शांगफू की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता होने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है, 'दोनों देशों के नेताओं के मार्गदर्शन में और दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बैठक की उपलब्धियों के आधार पर, दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक माध्यम से निकट संपर्क और संवाद बनाए रखने, चीन-भारत सीमा के पश्चिमी खंड पर प्रासंगिक मुद्दों के निपटारे में तेजी लाने, सीमाई इलाकों में अमन-चैन बनाए रखने पर सहमत हुए।'' चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को बीजिंग में मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों ने प्रासंगिक मुद्दों के समाधान में तेजी लाने पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया। निंग ने कहा, 'दोनों देशों के नेताओं की महत्वपूर्ण आम समझ के अनुसार, दोनों पक्षों ने प्रासंगिक मुद्दों के समाधान में तेजी लाने पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया।''

विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) के साथ 'प्रासंगिक' मुद्दों के समाधान पर दोनों पक्षों ने 'स्पष्ट और गहन' चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'दोनों पक्ष करीबी संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर काम करने पर सहमत हुए।'

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600